कांग्रेस रोकती रही लेकिन मोदी ने लोकपाल की नियुक्ति का वादा पूरा किया

आठ सदस्यीय लोकपाल मंडल नियुक्त हो जाने पर उसे अपने काम से यह सिद्ध करना होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर निचले सरकारी अधिकारी तक के भ्रष्टाचार की वह कलई खोलने में कोई लिहाजदारी नहीं करेगा।

आखिर लोकपाल की नियुक्ति हो ही गई। इस आंदोलन की शुरुआत अब से लगभग पचास साल पहले सांसद डॉ. लक्ष्मीमाल्ल सिंघवी और डॉ. सुभाष कश्यप ने की थी और फिर यही आंदोलन दस साल पहले अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने चलाया था। जरा गौर करें कि इस आंदोलन को चलाने वाले लोग कभी सत्तारुढ़ नेता नहीं रहे। वे मूलत: समाज सुधारक रहे हैं। सत्ता की राजनीति में उलझे हुए नेता भला लोकपाल की स्थापना क्यों होने देते। आज के जमाने में भ्रष्टाचार किए बिना कोई प्रधानमंत्री तो क्या, पार्षद भी नहीं बन सकता।

नरेंद्र मोदी सरकार ने भी पांच साल तक लोकपाल की नियुक्ति को उसी तरह झुलाए रखा जैसे अन्य दलों की सरकारें झुलाती रहीं। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डंडा चलाया तो झक मारकर लोकपाल नियुक्त करना पड़ा। इस नियुक्ति में भी कांग्रेस ने असहयोग किया। उसके नेता इसलिए चयन समिति की बैठक में नहीं गए कि उन्हें 'विशेष आमंत्रित' के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा में 'विपक्ष' की मान्यता नहीं है।

इसका अर्थ यह भी हुआ कि देश के इस प्रथम लोकपाल को भी राजनीति में घसीटा जाएगा। कहा जाएगा कि यह भाजपा का लोकपाल है। जो भी हो, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज पीसी घोष से देश आशा करेगा कि वे अपना काम पूरी निष्पक्षता और निडरता से करेंगे। आठ सदस्यीय लोकपाल मंडल नियुक्त हो जाने पर उसे अपने काम से यह सिद्ध करना होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर निचले सरकारी अधिकारी तक के भ्रष्टाचार की वह कलई खोलने में कोई लिहाजदारी नहीं करेगा। वह सीबीआई की तरह पिंजरे का तोता सिद्ध नहीं होगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग से भी ज्यादा सख्त होना होगा। मोदी सरकार को बधाई कि उसके हाथों यह महान संस्था कायम हुई। स्वीडन में 'ओम्बड्समेन' के नाम से यह संस्था पिछले 300 साल से काम कर रही है। इसने स्वीडन और नार्वे के अलावा कई यूरोपीय राष्ट्रों में सार्थक काम करके दिखाया है। आशा की जाए कि भारत का लोकपाल हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी आदर्श और प्रेरणा का काम करेगा।–डॉ. वेदप्रताप वैदिक

श्वेतवाद को दोबारा यूरोप में स्थापित करने के लिए हुआ न्यूजीलैंड में हमला

ये लोग श्वेतवाद को दोबारा से यूरोप में स्थापित करना चाहते हैं और एशियाई और अफ्रीकी लोगों के यूरोप में बसने के खिलाफ हैं। देखा जाये तो न्यूजीलैंड की घटना 'अति दक्षिणपंथी विचारधारा' के दुनिया भर में पांव पसारने का सबसे पुख्ता सबूत है।

न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों पर हुई गोलीबारी में 50 लोगों के मारे जाने के बाद से दुनिया भर में श्वेत श्रेष्ठता ग्रंथि और इस्लामोफोबिया शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है। न्यूजीलैंड में गोलीबारी के आरोपी ब्रिटिश मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रैंटन टैरेंट जैसी मानसिकता वाले आज बहुत से लोग हैं जोकि मानते हैं कि यूरोप में मुसलमानों के बस जाने से कई तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये लोग श्वेतवाद को दोबारा से यूरोप में स्थापित करना चाहते हैं और एशियाई और अफ्रीकी लोगों के यूरोप में बसने के खिलाफ हैं। देखा जाये तो न्यूजीलैंड की घटना 'अति दक्षिणपंथी विचारधारा' के दुनिया भर में पांव पसारने का सबसे पुख्ता सबूत है।

मुस्लिमों के साथ खड़ा हुआ पूरा न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड सहित जहाँ पूरा विश्व इस घटना के बाद से दहला हुआ है वहीं यह देखना सुखद लगा कि मुस्लिम समुदाय के साथ पूरे न्यूजीलैंड ने एकजुटता दिखाई। शुरुआत न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने की। उन्होंने गत सप्ताह हिजाब पहन कर दो मस्जिदों पर हुए आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि यह वह न्यूजीलैंड नहीं है, जिसे लोग जानते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के हिजाब पहनने की पहल को देश की महिलाओं ने जबरदस्त रूप से सराहा। समूचे देश की महिलाओं ने हिजाब पहनकर मुस्लिमों के प्रति एकजुटता दिखायी। महिलाओं ने कहा कि इस्लाम की विचारधारा को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक को पहनकर हमें इसके मायने पता चले और खुद को अल्पसंख्यक वर्ग का हिस्सा महसूस किया। महिला पुलिसकर्मियों और गैर मुस्लिम महिलाओं ने भी हिजाब पहना था। इनमें से कई महिलाओं ने पहली बार हिजाब पहना था। महिलाओं ने ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं। क्राइस्टचर्च में अल नूर मस्जिद के इमाम ने भी कहा है कि न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों पर हुए भयानक हमले ने देशवासियों का दिल भले ही तोड़ दिया है लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है। हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए शुक्रवार को अजान का सीधा प्रसारण किया गया।

उधर, मुस्लिम देशों ने भी इस्लाम को लेकर फैलाए जा रहे डर के खिलाफ "वास्तविक" कदम उठाए जाने की अपील की है। 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन' (ओआईसी) के मंत्रियों ने इस्तांबुल में एक बैठक के बाद कहा कि इस्लामोफोबिया (इस्लाम को लेकर डर) से उत्पन्न हिंसा के खिलाफ "वास्तविक, व्यापक और व्यवस्थित उपाय की आवश्यकता है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।" ओआईसी ने कहा कि मस्जिदों पर हमले और मुस्लिमों की हत्याएं इस्लाम के खिलाफ घृणा के 'अमानवीय और भयानक परिणाम' दर्शाती हैं। ओआईसी ने कहा कि मुस्लिम समुदायों, अल्पसंख्यकों या प्रवासियों वाले देशों को ऐसे बयानों और प्रथाओं से बचना चाहिये जो इस्लाम को आतंक, उग्रवाद और खतरे से जोड़ते हैं।

असाल्ट राइफलों और सेमी-ऑटोमेटिक हथियारों पर प्रतिबंध

अब चर्चा कर लेते हैं न्यूजीलैंड में हो रही कार्रवाइयों के बारे में। देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्राइस्टचर्च आतंकी हमले के मद्देनजर देश में असाल्ट राइफलों और सेमी-ऑटोमेटिक हथियारों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा, "मैं यह घोषणा कर रही हूं कि न्यूजीलैंड सभी सेमी ऑटोमेटिक हथियारों की बिक्री पर रोक होगी। हम सभी असॉल्ट राइफलों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च क्षमता वाली मैगजीन और राइफल से की जाने वाली गोलीबारी को तीव्र बनाने वाले सभी डिवाइस को बेचने पर भी प्रतिबंध होगा।

सोशल मीडिया पर भी उठे सवाल

न्यूजीलैंड की घटना ने सोशल मीडिया को लेकर भी कई तरह की चिंताएं पैदा की हैं। दरअसल इंटरनेट की दुनिया जहां राहत देती है वहीं आफत भी देती है। आज सोशल मीडिया पर ऐसे कई समूह देखे जा सकते हैं जहां आप्रवासियों, इस्लाम, नस्ल और वर्ण आदि के खिलाफ विरोधी बातें कही जाती हैं और इस बात का प्रचार प्रसार किया जाता है कि श्वेत आबादी ही श्रेष्ठ है। ब्रैंटन टैरेंट ने हमले के पहले 'दि ग्रेट रिप्लेसमेंट' शीर्षक से एक सनसनीखेज मैनिफेस्टो लिखा जिसमें उसने हजारों यूरोपीय नागरिकों की आतंकी हमलों में गई जान का बदला लेने के साथ श्वेत वर्चस्व कायम करने के लिए आप्रवासियों को बाहर निकालने की बात कही थी। यही नहीं उसने गोलीबारी की घटना का लाइवस्ट्रीम भी किया था।

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोशल मीडिया के खतरे से निपटने के लिए भी वैश्विक स्तर पर कदम उठाए जाने की अपील की है। फेसबुक के मुताबिक गोलीबारी की घटना के लाइवस्ट्रीम को 200 से कम बार ही देखा गया लेकिन उसे इस नरसंहार के फुटेज के तौर पर वायरल हुए करीब 15 लाख वीडियो हटाने पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह केवल न्यूजीलैंड का मुद्दा नहीं है, सोशल मीडिया के मंच का इस्तेमाल हिंसा और हिंसा को भड़काने वाली चीजों के प्रसार के लिए किया जा रहा है। हम सबको एकजुट होने की जरूरत है।

ब्रेंटन टैरेंट का क्या होगा ?

हत्यारे ब्रेंटन टैरेंट ने की बात करें तो वह अल-नूर और लिनवुड मस्जिदों में 50 लोगों की हत्या करने और दर्सियों अन्य को घायल करने के सिलसिले में एक मामले में आरोपित है। मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि वह नॉर्वे के हत्यारे एंडर्स ब्रेविक के संपर्क में भी रह चुका है, जिसने जुलाई 2011 में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए 75 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। अब माना जा रहा है कि ब्रेंटन टैरेंट को दोषी करार दिए जाने पर उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी और उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उसे जेल में सबसे अलग-थलग रखा जा सकता है। न्यूजीलैंड में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है और हमलावर टैरेंट यदि जनसंहार का दोषी करार दे दिया जाता है तो उसे जेल की रिकॉर्ड सजा का सामना करना पड़ सकता है। फौजदारी मामलों के वकील साइमन कलेन ने भी बताया कि दोषी करार दिए जाने पर उसे पैरोल के बगैर उम्रकैद हो सकती है। ऐसी सजा न्यूजीलैंड में "अभूतपूर्व" होगी।